

(9)

संख्या ४५३ / ११ (२) / ११-०३(बजट) / २०१०

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-१,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

देहरादून, दिनांक २३ मार्च, 2011

विषय:- वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के आय-व्ययक एवं प्रथम अनुपूरक मांग में आयोजनागत पक्ष में पुनर्विनियोग के द्वारा धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं-८१४९/०१ बजट (निर्माणाधीन मार्ग कार्य-रा०से०) / २०१०-११ दिनांक 11-03-2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अनुदान सं-२२ के लेखाशीषक-५०५४ सङ्क/भवन/सेतु कार्यों का प्रतिकर एवं एन०पी०वी० भुगतान, ४०५९-लोक निर्माण भवन-चालू कार्य तथा ४०५९-पूल्ड आवास योजना-चालू कार्य की मद में संलग्न बी०एम०-१५ के विवरणानुसार लेखाशीषक-५०५४ निर्माणाधीन मार्ग कार्य के अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में से ₹ ३०.०० करोड़ (₹ तीस करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यावर्तित करते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण अधिकारी द्वारा बी०एम०-८ प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह के व्यय का विवरण अनुवर्ती माह की ५ तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-१३ के प्रस्तर-११६ की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-१२८ की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो०नि.वि०) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की २५ तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा। प्रशासनिक विभाग बजट मैनुअल के प्रस्तर-१३० के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(ii)- आयोजनागत पक्ष की उक्त योजनाओं की सी०सी०एल० प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी साख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी०सी०एल० निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर ठोस कारण न होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी०सी०एल० निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का यह भी दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी०सी०एल० निर्गत करेंगे।

(iii)- सर्वप्रथम उन निर्माणाधीन कार्यों का पूर्ण किया जाय, जिसमें 75 प्रतिशत का कार्य पूर्ण हो चुका है। तत्पश्चात् 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुके कार्यों का वरीयता दी जाये।

(iv)- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग- । के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आवश्यकता होने पर ही आहरित एवं वितरित की जायेगी।

(v)- इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-१, उत्तराखण्ड शासन के पत्र- 187 / XXVII(1)/10 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मौलि

(vi)– उत्तराखण्ड में लागू समस्त वित्तीय नियमों तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अधीन ही समस्त प्रक्रियाये पूर्ण की जायेंगी तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

(vii)– साख सीमा मानक के अनुसार प्रत्येक ब्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख सीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस सम्बन्ध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(viii) साख सीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाय एवं उसका पूर्ण विवरण बी०एम० के प्रस्तर-17 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix)– जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(3)– यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या— 955/XXVII(2)/2010 दिनांक: 22 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव।

संख्या— 1413 (1) / 111(2) / 11-03(बजट) / 2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2— आयुक्त, गढ़वाल/कुमायू मंडल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3— समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
- 4— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5— मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 6— वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7— नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 8— निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9— लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
महिमा
(महिमा)
अनु सचिव।

प्रिय निपत्रक अधिकारी, मुख्य अमीरपत्रा ट्रस्ट-। लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीयक विभाग, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।

1

बजट प्राविधान व लेखाशीर्षक का विवरण	मानक भवतार अन्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष (सिरलास)	आवश्यक अनुमानित व्यय	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है	पुनर्विनियोग के परचात कलम-5 की कालम-1 कुल धनराशि धनराशि	पुनर्विनियोग के परचात कलम-1 कालम-1 की कुल धनराशि
01	02	03	04	05	06	07
पंजी लेखा:						
5054— सङ्क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय						
04— जिला तथा अन्य सङ्क						
800— अन्य व्यय						
03— राज्य संसद						
01— चालू निर्माण कार्य						
24— वृहत् निर्माण कार्य						
पंजी लेखा:						
(i) 5054— सङ्क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय						
04— जिला तथा अन्य सङ्को						
800— अन्य व्यय						
05— सङ्क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण						
00— 24— वृहत् निर्माण कार्य						
स्थानान्तरित धनराशि						
260000						
(ii) 4059— सङ्क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय						
80— सामाच						
800— अन्य भवन						
10— लोक निर्माण (चालू कार्य)						
00— 24— वृहत् निर्माण कार्य						
स्थानान्तरित धनराशि						
15000						
(iii) 4059— सङ्क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय						
80— सामाच						
800— अन्य भवन						
12— पूँज आवास योजना, (चालू कार्य)						
00— 24— वृहत् निर्माण कार्य						
स्थानान्तरित धनराशि						
25000						
आवश्यकता होने के कारण।						
बजट प्राविधान						
3380000 2245486 834514 300000(क)						
स्थानान्तरित धनराशि						
300000 (ख) 790000 3080000						

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग में बजट के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित प्राविधिकों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(महिमा)
अनु सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुशासन-2

यूओ० संख्या— ७५५(१) / xxvii(२) / २०१०

देहरादून दिनांक: २२ मार्च, २०११

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

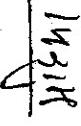
महालेखाकार, उत्तराखण्ड,
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा,
देहरादून ।

संख्या— ४१३ (१) / ११(२) / ११-०३(बजट) / २०१० तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1— मुख्य/वरिष्ठ कोषधिकारी, जनपद देहरादून।
- 2— मुख्य अधिकारी स्तर-१, लो०निलि०, देहरादून।

(डॉ एम०सी० जोशी)
अपर सचिव, वित्त।


(महिमा)
अनु सचिव।